भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2111

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-709 एडी का चौड़ीकरण

2111. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फरनगर जिले के बुढाना और खतौली विधान सभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाला दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह से कार्यशील कर दिया जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने शामली से मुजफ्फरनगर होते हुए बिजनौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-709 एडी को चौड़ा करने के कार्य की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और उक्त राजमार्ग को पूरा होने के लिए अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) क्या सरकार का मुजफ्फरनगर में कागज और भट्टी उद्योगों के भारी वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मार्गों पर शहर के भीतर यातायात संबंधी संकुचन को समाप्त करने के उद्देश्य से अलग सर्विस लेन या समर्पित ट्रक टर्मिनल का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का गन्ना किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की ऊंचाई और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के साथ अंडरपास और सर्विस रोड के डिजाइन और निर्माण में किसी प्रकार का तकनीकी संशोधन करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) दिल्ली-देहरादून पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग पूरा होने के करीब है और काम पूरा होने पर यातायात के लिए खुलने की संभावना है।

(ख) सरकार ने मौजूदा शामली से बिजनौर खंड को तीन पैकेजों में 4-लेन का काम शुरू किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) एनएच-709एडी का शामली से मुजफ्फरनगर खंड जनवरी 2024 में पूरा किया गया था।

(ii) एनएच-709एडी का मुजफ्फरनगर से मिरानपुर खंड अक्टूबर 2024 में पूरा किया गया था।

(iii) एनएच-34 का मिरानपुर से बिजनौर (बेहसुला से बिजनौर परियोजना का हिस्सा) खंड, जो निर्माणाधीन है और दिसंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

(ग) मुजफ्फरनगर बाईपास के संकुचन (डिकॉन्जेशन) के लिए, सरकार ने मुजफ्फरनगर बाईपास के शुरुआती बिंदु पर छह लेन के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कुल 419.47 करोड़ रूपये की पूंजीगत लागत के साथ एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, साथ ही 3.66 किमी स्लिप/सर्विस रोड का प्रावधान किया है।

(घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ट्रक टर्मिनल की आवश्यकता सहित वाहन यातायात की आवश्यकता का आकलन करती रहती है और कार्यान्वयन पर निर्णय साइट की आवश्यकताओं, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के संहिताओं (कोडों) और प्रकाशन के आधार पर लिया जाता है। अंडरपास सहित विभिन्न संरचनाओं की ऊंचाई को आईआरसी कोडल प्रावधान, साइट की स्थिति आदि के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है।

*****